

DILRMP एवं भू-अभिलेखों का डजिटिलीकरण

प्रलिस के लयि:

[राष्ट्रीय भूमरिर्कॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम \(NLRMP\)](#), [डजिटल इंडया भू-अभिलेख आधुनकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#), [गाँवों का सरवेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण \(SVAMITVA\) योजना](#)

मेन्स के लयि:

भू-अभिलेखों का डजिटिलीकरण, DILRMP योजना: लाभ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

[स्रोत: द प्रति](#)

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2024 तक **98.5%** ग्रामीण भू-अभिलेखों का डजिटिलीकरण कर दिया गया है, जससे पारदर्शता बढ़ने के साथ भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

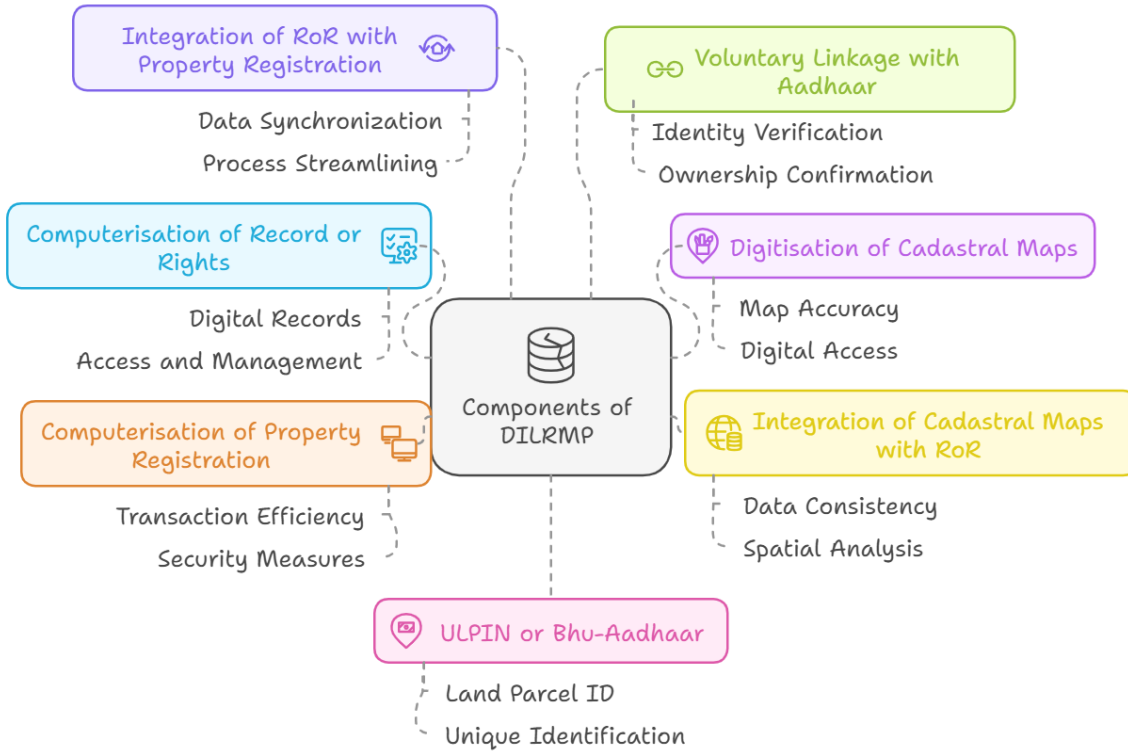
- यह उपलब्धवर्ष 2008 में शुरू किए गए [डजिटल इंडया भूमि अभिलेख आधुनकीकरण कार्यक्रम](#) का हसिसा है जसका उद्देश्य कृषि भूमि रिकॉर्ड को डजिटल तथा आधुनकी बनाना है ताकि इसकी पहुँच में सुधार होने के साथ इससे संबंधित ववादों में कमी आ सके।

नोट:

- [गाँवों का सरवेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगकी के साथ मानचित्रण \(SVAMITVA\) योजना](#), आवासीय क्षेत्रों से संबंधित भू-अभिलेख तैयार करने से संबंधित है, जसका उद्देश्य भूमि संबंधी ववादों का समाधान करना, [ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के आधार पर बैंक ऋण लेने में मदद करना](#) तथा ग्राम पंचायतों को विकास योजना बनाने तथा संपत्तिकर एकत्र करने में सहायता करना है।

डजिटल इंडया भू-अभिलेख आधुनकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) क्या है?

- राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) को वर्ष 2016 में पुनः आरंभ किया गया और इसका नाम बदलकर [डजिटल इंडया भू-अभिलेख आधुनकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#) कर दिया गया, जो केंद्र द्वारा 100% वत्तपोषण वाली एक [केंद्रीय क्षेत्रक योजना](#) है।
 - NLRMP एक [केंद्र प्रायोजित योजना](#) थी जसि वर्ष 2008 में देश में भूमि अभिलेख प्रणाली का आधुनकीकरण करने तथा स्वामत्त्व गारंटी के साथ [नरिणायक भूमि-स्वामत्त्व प्रणाली](#) को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।



■ DILRMP के अंतरगत प्रमुख पहल:

- **वशिष्ट भूमि पारसल पहचान संख्या (ULPIN):** ULPIN या " भू-आधार "प्रत्येक भूमि पारसल के लिये उसके भू-नरिदेशांक के आधार पर 14 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है।
 - 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वयित यह योजना रियल एस्टेट लेन-देन को सुव्यवस्थित करने, संपत्ति विवादों को सुलझाने एवं आपदा प्रबंधन प्रयासों में सुधार करने में सहायक है।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS):** NGDRS या ई-पंजीकरण द्वारा देश भर में वलिख/दस्तावेज़ पंजीकरण के लिये एक समान प्रक्रिया प्रदान की गई है जिससे ऑनलाइन प्रवर्षिट, भुगतान, नयुक्तियाँ एवं दस्तावेज़ खोज की सुविधा मिलती है।
 - अब तक 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनाया है तथा 12 अन्य ने राष्ट्रीय पोर्टल के साथ डेटा साझा किया है।
 - **ई-न्यायालय एकीकरण:** भू-अभिलेखों को ई-न्यायालय से जोड़ने का उद्देश्य न्यायपालिका को प्रामाणिक भूमि संबंधी जानकारी प्रदान करना, मामलों के त्वरित समाधान में सहायता करना और भूमि विवादों को कम करना है। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकरण को मंजूरी दे दी गई है।
 - **भू-अभिलेखों का लपियंतरण:** भू-अभिलेखों तक पहुँचने में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये, यह कार्यक्रम भूमि दस्तावेज़ों को भारतीय संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में लपियंतरित कर रहा है।
 - यह योजना 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही प्रयोग में है।
 - **भूमि सममान:** इस पहल के तहत, 16 राज्यों के 168 ज़िलों ने भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण और मानचित्र डिजिटलीकरण सहित कार्यक्रम के 99% से अधिक मुख्य घटकों को पूरा करने के लिये "प्लेटनिम ग्रेडिंग" हासिल की है।

LAND REFORMS IN RURAL AREAS

1988-89

Pilot project to digitise land records implemented in 8 districts

Computerisation of land records taken up in nearly 300 districts under 8th five year plan

1992-97

1997-08

digitisation of land records started in almost all states and UTs

National Land Record Modernization Programme (NLRMP) launched

2008

NLRMP revamped and renamed Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) with increased scope of work

2016

Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA) scheme was launched to give Record of Rights (RoR) for residential property in villages

2020

2021

Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) or bhu-Aadhaar and voluntary linkage of RoR with owner's Aadhaar number launched

ThePrint

भारत को डजिटल भूमरिक्ॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है?

परिचय:

- भूमि भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#) के अनुसार, भारत का 45% से अधिक कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जिसके लिये एक आधुनिक और पारदर्शी भूमरिक्ॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।
 - वर्ष 2008 में सरकार ने [NLRMP](#) शुरू किया, जिसका नाम वर्ष 2016 में DILRMP रखा गया।

डजिटल भू-अभिलेखों की आवश्यकता:

- समानता सुनिश्चित करना:** पारदर्शी भू-अभिलेखों से नष्पिक्ष भूमिसुधार संभव होता है, जिससे **भूमिहीनों और हाशिये** पर पड़े लोगों को लाभ मिलता है।
 - वे **महिलाओं और कमजोर समूहों** को उनके भूमि अधिकारों और संबंधित सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके सशक्त बनाते हैं।
- मुकदमेबाज़ी को कम करना:** भारत में भूमि विवाद **न्यायालयी मामलों में प्रमुख स्थान** रखते हैं, जिनमें **समय और धन दोनों खर्च** होते हैं। पारदर्शी भूमरिक्ॉर्ड प्रबंधन स्पष्ट, **सरकार समर्थित स्वामित्व अधिकार** सुनिश्चित करके **ववादों को कम** कर सकता है।
- विकास को बढ़ावा देना:** नविश और विकास के लिये भूमि एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है। सुव्यवस्थित भूमि अभिलेख प्रणालियाँ **लेन-देन के जोखिम को कम** करती हैं, नविश को प्रोत्साहित करती हैं, तथा **भूस्वामियों को ऋण और बीमा के लिये स्वामित्व का लाभ** उठाने में सहायता करती हैं।
- पारदर्शिता में सुधार:** भारत के भू-अभिलेख प्रायः **पुराने और बखिरे हुए** हैं। उन्हें **डजिटल बनाने और स्थानिक तथा आधार** जैसे अन्य डेटाबेस के साथ एकीकृत करने से सटीकता और पहुँच में वृद्धि हो सकती है, साथ ही **बेनामी संपत्तियों** की समस्या का समाधान भी हो सकता है।

DILRMP (भू-अभिलेखों का डजिटलीकरण) के लाभ:

- भू-अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार: DILRMP भूमि स्वामित्व और संव्यवहार अभिलेखों को **डजिटल बनाता है** तथा उन्हें **अद्यतन**

करता है, जिससे सटीकता, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिये उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके।

- मुकदमेबाजी और धोखाधड़ी में कमी: DILRMP का उद्देश्य सरकार समर्थित गारंटी के साथ एक नरिणायक भूमि-शीर्षक प्रणाली स्थापित करना, नरिणविवाद स्वामित्व सुनिश्चित करना, शीर्षक दोषों के वरिद्ध क्षतपूरत, और भारत में भूमि विवादों एवं धोखाधड़ी में कमी लाना है।
- वृद्धि एवं वकिस को बढ़ावा देना: DILRMP कुशल भूमि बाजार की सुवधि प्रदान करता है, लेन-देन के जोखमि को कम करता है, भूमि स्वामित्व का उपयोग करके ऋण तक पहुँच को सक्षम बनाता है, साथ ही कृषि, बुनियादी ढाँचे और आवास में निवेश, औद्योगिकरण एवं क्षेत्रीय वकिस को बढ़ावा देता है।

टपिपणी:

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने भू-अभलिख पोर्टल, यूपी भूलेख पर एक सुवधि आरंभ की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बदले लिये गए बैंक ऋण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

भूमि रिकॉर्ड डजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- भाषा और बोली संबंधी बाधाएँ: भारत की भाषाई वविधिता ग्रामीण आबादी की डजिटलीकरण की समझ में बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि किसान और भूस्वामी अपनी मूल भाषाओं में उपलब्ध न होने वाली डजिटल प्रणालियों से जुड़ते हैं, जिससे भ्रम और वरिध की भावना उत्पन्न होती है।
- सामुदायिक शेयरधारिता: कई पूर्वोत्तर राज्यों में, सामुदाय-आधारित भूमि स्वामित्व भू-अभलिखों के डजिटलीकरण और मानकीकरण को जटिल बना देता है, क्योंकि पारंपरिक प्रथाएँ अक्सर औपचारिक स्वामित्व प्रणालियों के साथ मतभेद उत्पन्न करती हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।
- जागरूकता का अभाव: DILRMP भूमि मालिकों, खरीदारों, वकिरेताओं और करियेदारों जैसे हतिधारकों की सक्रिय भागीदारी पर नरिभर करता है, लेकिन इनके बीच इसके लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव है।
- भू-अभलिखों की गुणवत्ता: अस्पष्ट भूमि शीर्षक और पुराने भूकर मानचित्र सटीक अभलिखों में बाधा डालते हैं, जनि पर नीति आयोग जोर देता है, ये प्रभावी योजना और संपत्ति अधिकारों की स्पष्टता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
 - भूकर मानचित्रों में प्रायः परिवारों या गाँवों के बीच भूमि का वभिजन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि स्वामित्व में हुए परिवर्तनों को राजस्व अभलिखों में अद्यतन नहीं किया जाता, जिससे व्यापक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- भूमि प्रबंधन प्रणालियों की जटिलता: भारत की जटिल भूमि प्रबंधन प्रणालियाँ, जिसमें अनेक वभिग और वनिथिमन शामिल हैं, नरिबाध डजिटलीकरण और हतिधारकों के संरेखण में बाधा डालती हैं।
- संसाधनों की कमी: DILRMP को अपर्याप्त धन, कर्मचारियों, बुनियादी ढाँचे के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, भू-अभलिखों को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाने के लिये संसाधनों और क्षमता नरिमाण में वृद्धि की आवश्यकता है।

आगे की राह

- भू-अभलिखों का एकीकरण: भूमि संबंधी सेवाओं तक नरिबाध पहुँच के लिये भू-अभलिखों को संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और सरकारी सब्सिडी से जोड़ने वाला एक एकीकृत मंच वकिसति करना।
- अभलिखों का अद्यतनीकरण: नथिमति ऑडिट और ड्रोन तथा उपग्रह इमेजरी के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित मानचित्रण के माध्यम से सटीक और अद्यतन भूमि अभलिख सुनिश्चित करना।
 - सामुदाय-आधारित पहल के माध्यम से भू-अभलिखों के सर्वेक्षण और अद्यतनीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, जहाँ नविसी भूमि की सीमाओं और स्वामित्व को सत्यापित करने, सटीकता सुनिश्चित करने तथा विवादों को कम करने में योगदान करते हैं।
- जन जागरूकता अभियान: स्थानीय मीडिया, सामुदायिक बैठकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके किसानों और भूमि मालिकों को ULPIN लाभों और डजिटल भूमि रिकॉर्ड तक पहुँच हेतु शकिसति करना।
- विवाद समाधान तंत्र: भारत में सभी दीवानी मामलों में से लगभग दो-तहियाँ मामले भूमि और संपत्ति से संबंधित होते हैं।
- समरपति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करके भूमि विवादों को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से हल करना, जहाँ प्रभावित पक्ष शकियातें प्रस्तुत कर सकें और उनकी समाधान प्रक्रिया पर नज़र रख सकें।
- नीतगित ढाँचा: एक व्यापक नीतगित ढाँचा वकिसति करना, जो भूमि प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण का समर्थन तथा स्थानीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता हो।
 - डजिटल प्लेटफॉर्म के डज़ाइन में उपयोगकर्त्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना, जो महिलाओं और हाशिये के समुदायों सहित सभी जनसांख्यिकी के लिये सहज और सुलभ हों।
- सार्वजनिक-नजि भागीदारी (PPP): प्रौद्योगिकी वकिस और कार्यान्वयन में वशिषज्जता का लाभ उठाने के लिये सरकारी एजेंसियों और नजि प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
 - भूमि डजिटलीकरण के संबंध में आउटरीच और शकिसा प्रयासों में सहायता के लिये ग्रामीण वकिस पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना।
- अनुसंधान एवं वकिस: नवीन प्रौद्योगिकियों (जैसे, सुरकषति भूमि लेनदेन के लिये ब्लॉकचेन) की खोज हेतु अनुसंधान एवं वकिस में निवेश करना, जिससे भू-अभलिखों की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हो सके।
 - डजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग में प्रभावी दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों और भूमि अभलिख अधिकारियों हेतु प्रशकिसण कार्यशालाएँ आयोजित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

